RNI No.: UPHIN/25/A1697
GARVI GUJARAT
गरवी गुजरात
गरवी गुजरात
लखनऊ से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 192
दि. 13.11.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : ASHWANI KUMAR Regd. Office: TF-01, Nanakram Super Market,Ramnagar,Sabarmati, Ahmedabad-380 005. Gujarat, India.
Phone : 90163 33307 (M) 93283 33307, 98253 33307 • Email : garvigujarat2007@gmail.com • Email : garvigujarat2007@yahoo.com • Website : www.garvigujarat.co.in

सरदार पटेल राष्ट्र देवता...स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य ने की तगड़ी तारीफ, क्या बोले सीएम योगी?

लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150 जयंती के मौके पर गुजरात के केवडिया में चल रहे भारत पर्व में बुधवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। उनके साथ यूपी के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी इस आयोजन का हिस्सा बने।

अहमदाबादः (एजेंसी)। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर बुधवार का दिन उत्तर प्रदेश के नाम रहा। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने पुष्पांजलि अर्पित की। यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम ने इसके बाद केवडिया में भारत पर्व के मौके पर आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरदार पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आज एकता नगर आने का सौभाग्य मिला है। अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हमें अपने भारत के अंदर 535 अलग देश के लिए वीजा बनवाकर जाना पड़ता। सरदार पटेल जी एक राष्ट्र के देवता के रूप में हैं मैं उनको नमन करता हूं और श्रद्धांजलि देता हूं और पीएम मोदी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस वैसे एकता दिवस कार्यक्रम को 31 अक्टूबर के लिए शुरू किया है।

क्या बोले ब्रजेश पाठक?

यूपी के डिप्टी सीएम आज भारत पर्व केवडिया गुजरात में सबसे बड़े पर्यटक स्थल पर आज हम सब एकत्र हुए हैं। भारत पर्व पर मैं पूरे

प्रदेशवासियों और भारतवर्ष को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। जिस ढंग से गुजरात का केवडिया धाम बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित हुआ है।

और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति सरदार साहब की लगाई गई है। मैं ऐसे अवसर पर सरदार वल्लभभाई पटेल को नमन करता हूं और गुजरात सरकार का आभार प्रकट करता हूं और विशेष आभार और अभिनंदन पीएम मोदी को करता हूं कि उन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल की स्मृतियों संजोते हुए उन्होंने विरासत का एक बड़ा सम्मान करने का काम किया है।

क्या बोले सीएम योगी आदित्यनाथ?

भारत पर्व के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गुजरात सदैव देश को एक राह दिखाने वाला राज्य रहा है...गुजरात भगवान सोमनाथ और भगवान नागेश्वर नाथ की पावन धरा है। यह भारत की आध्यात्मिक विरासत की भूमि भी है। यह भारत के स्वाधीनता आंदोलन को स्वदेशी से स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने वाली पावन धरा भी है।

पीएम मोदी ने संभव कर दिखाया

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नया भारत', सुरक्षा, संप्रभुता और अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है, जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा, उसकी कीमत चुकाएगा। सीएम योगी ने कहा कि जो दूसरों के लिए असंभव था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे संभव करके दिखाया। सीएम योगी ने कहा कि गुजरात भारत की अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष, 'भारत रत्न' सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की पावन धरा है। योगी आदित्यनाथ के साथ इस दौरे में यूपी विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना भी मौजूद रहे।

15 नवंबर तक चलेगा भारत पर्व

केवडिया में भारत पर्व 15 नवंबर तक चलेगा। इसकी शुरूआत 1 नवंबर से हुई थी। इससे पहले 31 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एकता दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे थे। गुजरात के कैबिनेट मंत्री अर्जुन मोढवाडिया ने सभी का स्वागत किया। इस मौके पर सीईओ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अमित अरोड़ा ने यूपी के सीएम और उप मुख्यमंत्रियों को स्मृति चिन्ह भेंट किए। सीएम योगी के दौरे में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री जयवीर सिंह साथ में मौजूद रहे।

प्रधानमंत्री ने एलएनजेपी अस्पताल का दौरा किया, विस्फोट पीड़ितों से मुलाकात की

प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया कि दोषियों को सजा दी जाएगी

(एजेंसी)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल जाकर हाल ही में लालकिले के पास हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। उन्होंने पीड़ितों और उनके परिवारों से बातचीत की और उनके इलाज के बारे में जानकारी ली। श्री मोदी ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना भी की।

विस्फोट घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने जोर देकर कहा, "षड्यंत्र के पीछे जो लोग हैं, उन्हें सजा दी जाएगी।"

एक्स पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहाः

"एलएनजेपी अस्पताल जाकर दिल्ली में हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिला। सभी के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं।"

इस षड्यंत्र के पीछे जो लोग हैं उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जाएगा!

अल्पसंख्यक कार्य सचिव ने छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत चलाई जा रही परियोजनाओं की समीक्षा की

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने छत्तीसगढ़ में

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (पीएमजेवीके) के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान, सचिव ने राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति पंजीकरण की स्थिति की भी समीक्षा की। इसके अतिरिक्त, राज्य में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम की पहलों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में नोटरी के रूप में चयनित 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को प्रमाणपत्र प्रदान किए, नोटरी पोर्टल लॉन्च किया गया

- गुजरात राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी तथा विधि राज्य मंत्री श्री कौशिक वेकरिया सहभागी हुए

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेलः-

- कानूनी प्रक्रिया में कॉन्फिडेंस, सिक्योरिटी तथा ऑनेस्टी स्थापित कर विकास को गति देने में नोटरी की भूमिका महत्वपूर्ण है
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'जस्टिस टु ऑल, अपीजमेंट टु नन' मंत्र साकार हो रहा है
- सरकारी सेवाएँ सुदूरवर्ती नागरिक तक मोबाइल के एक क्लिक से पहुँचाने का प्रधानमत्री का लक्ष्य
- दस्तावेज अपलोड करने तथा आवेदन का स्टेटस जानने की समग्र प्रक्रिया अब ऑनलाइन, समय एवं शक्ति की बचत से कार्यक्षमता बढ़ेगी
- नोटरी की समग्र कार्यवाही का चरणबद्ध डिजिटलाइजेशन होने से पर्यावरण की रक्षा होगी, पेपरलेस गवर्नेंस को वेग मिलेगा
- गुजरात के इतिहास में पहली बार 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को नोटरी के रूप में नियुक्ति दी गई : उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष संघवी

गांधीनगर, 12 नवंबर :मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य सरकार के विधि विभाग तथा गुजरात बार काउंसिल के संयुक्त उपक्रम से नोटरी (लेख्य प्रमाणक) के रूप में चयनित 1500 से अधिक अधिवक्ताओं को बुधवार को गांधीनगर में आयोजित कार्यक्रम में प्रमाणपत्र प्रदान किए।

श्री पटेल ने राज्य में ई-नोटरी सिस्टम विकसित करने के लिए नोटरी पोर्टल को लॉन्च करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने साधारण व्यक्ति के हित को तथा उसकी सरलता

को ईज ऑफ लिविंग के केन्द्र में रखा है। उन्होंने भर्ती प्रक्रिया या याजोनाओं के लाभ वितरण में पारदर्शिता के साथ मैक्सिमम गवर्नेंस-मिनिमम गवर्नमेंट का शासन मंत्र अपनाया है। यह कार्यक्रम गुजरात के विधि जगत में आज उसी मंत्र को साकार करने वाला अवसर है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राष्ट्र या राज्य के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए विधि (कानून) का शासन महत्वपूर्ण नींव है। प्रधानमंत्री ने कानून के शासन के लिए समयानुरूप कानून प्रस्तुत करने का भगीरथ कार्य किया है। उन्होंने अंग्रेजों के समय के अनावश्यक कानूनों को निरस्त कर कानूनी प्रक्रिया सरल बनाई है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 'जस्टिस टु ऑल, अपीजमेंट टु नन' मंत्र साकार हो रहा है। ट्रिपल तलाक निषेध, धारा 370 निर्मूलन तथा भारतीय न्याय संहिता का सुचारु कार्यान्वयन उनके मार्गदर्शन में हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वैधानिक प्रक्रिया में विश्वास, सुरक्षा तथा प्रामाणिकता स्थापित कर विकास को गति देने में नोटरी के रूप में भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री पटेल ने जोड़ा कि वैधानिक प्रणाली तथा अर्थव्यवस्था में विश्वास का निर्माण करने के लिए दस्तावेजों की ऑथेंटिसिटी का दायित्व नोटरी के सिर होता है। नोटरी द्वारा नोटराइज किए गए दस्तावेजों को कानूनी मान्यता मिलती है तथा कोर्ट एवं अन्य स्थानों पर इन दस्तावेजों की स्वीकृति सरल बनने से लोगों का ईज ऑफ डूइंग भी बढ़ता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश में आम आदमी को मिलने वाली सेवा सुविधाओं में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का नया युग शुरू करवाया है। सरकारी सेवाएँ सुदूरवर्ती नागरिक तक मोबाइल के एक क्लिक से पहुँचाने का प्रधानमंत्री ने लक्ष्य रखा है। उन्होंने डिजिटल भारत अंतर्गत डिजिटल माध्यमों से सरकारी सेवाओं की पारदर्शी पहुँच को सुनिश्चित किया है। उनके दिशादर्शन में वैधानिक व्यवस्थाओं को आधुनिक बनाने के लिए डिजिटलाइजेशन पर बल दिया गया है।

उन्होंने नोटरी पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि आज गुजरात में शुरू हुआ नोटरी पोर्टल प्रधानमंत्री के डिजिटल भारत के सपने को साकार करने वाला एक और कदम है। नए पोर्टल के फलस्वरूप नोटरी की नियुक्ति तथा आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी। सभी को समान एवं न्यायी अवसर भी मिलेंगे। दस्तावेज अपलोड करने और आवेदन का स्टेटस जानने की समग्र प्रक्रिया अब ऑनलाइन हो जाएगी, जिससे नोटरी की सेवा लेने में लगने वाले समय एवं शक्ति की बचत से कार्यक्षमता बढ़ेगी।

उन्होंने कहा कि नोटरी पोर्टल से लीगल डॉक्यूमेंट भविष्य में सुरक्षित एवं प्रमाणित करने के साथ वर्षों तक उनका सेंट्रल रिकॉर्ड संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने इस बात का विशेष उल्लेख किया कि नोटरी की समग्र कार्यवाही का चरणबद्ध ढंग से डिजिटलाइजेशन होने से कागज का उपयोग घटेगा व पर्यावरण की रक्षा होगी, जिससे पेपरलेस गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट को वेग मिलेगा।

वित्तीय सेवा सचिव ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की

बैंकों ने स्थिर वृद्धि, बेहतर परिसंपत्ति गुणवत्ता और मजबूत डिजिटल प्रदर्शन दर्ज किया

(एजेंसी)।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में ₹93,675 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया; सकल एनपीए घटकर कई वर्षों के निचले स्तर 2.30% और शुद्ध एनपीए 0.45% पर आ गया, कुल कारोबार ₹261 लाख करोड़ रहा

कम लागत वाली जमाओं में वृद्धि को बनाए रखते हुए और जोखिम प्रबंधन को मजबूत करते हुए एमएसएमई और कृषि को ऋण में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित किया गया

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग, साइबर सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा, हरित अवसंरचना, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन और डेटा सेंटर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में ऋण विस्तार शामिल हैं

जनसमर्थ पोर्टल पर स्टार्टअप ऋण मॉड्यूल लॉन्च किया गयाः विकसित भारत @2047 की दिशा में रोडमैप को दशार्ती सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मंथन 2025 पर रिपोर्ट जारी की गई

प्रविष्टि तिथिः 12 ठडश 2025 6:53ढट ु८ ढक्ह ऊँ

वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) के सचिव, श्री एम. नागराजू ने आज नई दिल्ली में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रबंध निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के लिए उनके प्रदर्शन का आकलन किया गया। बैठक में वित्तीय प्रदर्शन, परिसंपत्ति गुणवत्ता, वसूली और समाधान, डिजिटल परिवर्तन और सरकारी प्रमुख योजनाओं की प्रगति सहित प्रमुख क्षेत्रों की समीक्षा की गई। यूआईडीएआई ने डिजिटल पहचान एकीकरण और डी-डुप्लीकेशन के लिए आधार के उपयोग पर एक प्रस्तुति दी। बैंकिंग में मानव एआई अभिसरण विषय पर भी चर्चा हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही के दौरान ₹93,675 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया, जो साल-दर-साल स्थिर वृद्धि को दशार्ता है। सितंबर 2025 तक कुल कारोबार ₹261 लाख करोड़ रहा, जिसमें अग्रिमों में 12.3 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) और जमाओं में 9.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की वृद्धि हुई। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का सकल एनपीए अनुपात घटकर 2.30 प्रतिशत और शुद्ध एनपीए 0.45 प्रतिशत रह गया, जो परिसंपत्ति गुणवत्ता में निरंतर सुधार को दशार्ता है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम के छात्रों के पहले दल के साथ बातचीत की

केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने उन्हें 'एक भारत श्रेष्ठ भारत' की भावना को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया

(एजेंसी)।

केंद्रीय संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया ने आज अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्रों के पहले दल के साथ वर्चुअल माध्यम से बातचीत की। इस सत्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास सचिव, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास संयुक्त सचिव और राजीव गांधी विश्वविद्यालय (आरजीयू) के कार्यवाहक कुलपति और कुलसचिव भी उपस्थित थे।

कार्यक्रम के उद्घाटन संस्करण में 39 छात्र शामिल हुए। इनमें से 19 गोवा से और 20 उत्तराखंड से थे। यह पहले दल के रूप में अरुणाचल प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय और राजीव गांधी विश्वविद्यालय इनकी मेजबानी कर रहा है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) और पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) द्वारा आयोजित और वित्तपोषित अष्टलक्ष्मी दर्शन युवा आदान-प्रदान कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं के बीच संपर्क को मजबूत करना, अंतर-क्षेत्रीय समझ को बढ़ावा देना और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की "एक भारत श्रेष्ठ भारत" पहल के दृष्टिकोण के अनुरूप सांस्कृतिक सराहना को बढ़ावा देना है। इस आदान-प्रदान कार्यक्रम में 28 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 40 बैचों में 1280 छात्र शामिल हैं। ये सभी पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेंगे।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम की संकल्पना करते समय लड़के और लड़कियों की समान भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार का संकल्प था। यह समावेशिता और सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। उन्होंने अष्टलक्ष्मी दर्शन को एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत एक विशिष्ट सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान-प्रदान पहल बताया।

इसका उद्देश्य देश और आठ पूर्वोत्तर राज्यों के युवाओं के बीच भावनात्मक और सांस्कृतिक बंधन को मजबूत करना है। यह कार्यक्रम छात्रों को क्षेत्र की भाषाओं, परंपराओं, पर्यावरण और सामुदायिक जीवन को अनुभव करने का अवसर प्रदान करता है। इससे उन्हें देश की संपूर्ण विविधता और एकता को अनुभव करने में मदद मिलती है।

जीरो घाटी की अपनी हालिया यात्रा पर इसके शांत आकर्षण का उल्लेख करते हुए श्री सिंधिया ने कहा कि ऐसा लगा जैसे "समय इतना धीमा हो गया हो कि आप धरती की आवाज सुन सकें।" छात्रों ने भी घाटी और ईटानगर की अपनी यात्राओं पर मिलते-जुलते अनुभव साझा किए।

सम्पादकीय

पाक सेना प्रमुख की शक्तियां संवैधानिक रूप से बढ़ीं

पाकिस्तान का इतिहास सैन्य शासन से भरा हुआ है। यहां चुनी हुई सिविलयन सरकार थोड़ा समय चलती है फिर कोई न कोई जनरल शासन का तख्ता पलट देता है। ताजा उदाहरण पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ही ले लीजिए। पाकिस्तान में शाहबाज शरीफ की सरकार भारत के ऑपरेशन सिदूर से सबक लेते हुए संवैधानिक बदलाव की तैयारी में है। जिसमें सेना प्रामुख आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिपेंस फोस्रेस (सीडीएफ) बनाने की योजना है, इससे उनकी शक्तियां संवैधानिक रूप से बढ़ जाएंगी। पाकिस्तान की शाहबाज शरीफ ने लगता है कि एक बार फिर अपने सेना प्रामुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने का पैसला किया है। 8 नवम्बर को संसद में पेश 27वें संवैधानिक संशोधन विधेयक के जरिए रक्षा बलों के प्रामुख (चीफ ऑफ डिपेंस फोस्रेस) सीडीएफ नामक एक नया अत्यंत शक्तिशाली पद सृजित कर दिया गया, जो सीधे मुनीर के लिए ही रचा गया प्रातीत होता है। यह पदोन्नति मई 2025 में भारत के साथ हुए चार दिवसीय संघर्ष के बाद मिले फील्ड मार्शल के सम्मान के ठीक छह महीने बाद हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आतंकवाद के कथित संरक्षक मुनीर को यह दोहरी मेहरबानी आखिर क्यों? क्या मई का संघर्ष ही वह कारनामा है या फिर पाकिस्तान की आंतरिक अस्थिरता और सैन्य तानाशाही को मजबूत करने की साजिश? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुनीर को ओसामा बिन लादेन इन सूट कहा जाता है और अब यह प्रामोशन उसके दोहरे चेहरे–एक तरफ आतंक के प्रायोजक, दूसरी तरफ क्षेत्रीय स्थिरता के हामी–की ओर उजागर कर रहा है। संवैधानिक संशोधन : मुनीर की कमान को संवैधानिक छतरी लेकिन लोकतंत्र पर सहमे कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने वैबिनेट की मंजूरी के बाद सीनेट में पेश किए गए इस विधेयक में संविधान के अनुच्छेद 243 में व्यापक बदलाव प्रास्तावित है, जो सशस्त्र बलों की कमान संरचना को पूरी तरह पुनर्गठित कर देते हैं। यह 27वां संविधान विधेयक पाकिस्तान के संविधान में एक बड़ा बदलाव लाने वाला प्रास्तावित कानून है। इस संशोधन में अनुच्छेद 243 संशोधन भी शामिल है, जिसके तहत रक्षा बलों के प्रामुख का पद औपचारिक रूप से सेना प्रामुख को सौंप दिया जाएगा और उन्हें आजीवन फील्ड मार्शल का पद प्रादान किया गया है। अगर यह बिल पास हुआ तो सेना प्रामुख आसिम मुनीर आजीवन फील्ड मार्शल के पद पर रहेंगे। हालांकि इसका विपक्ष पुरजोर विरोध कर रहा है। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि यह बदलाव देश की रक्षा आवश्यकताओं और सैन्य कमानसंर चना को आधुनिक बनाने के लिए किया जा रहा है। पाकिस्तान ने सीडीएफ का जो मसौदा पेश किया है, वह भारत के चीफ डिपेंस ऑफ आमा स्टॉफ (सीडीएस) के प्रारूप की चोरी की है। मजलिस–ए–वहदत–एमुस्लेमीन पार्टा प्रामुख अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा है कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक संस्थाएं पंगू हो चुकी हैं। राष्ट्र को (प्रास्तावित) 27वें संशोधन के खिलाफ कदम उठाना चाहिए।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में किसान भाई-बहनों को 'पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार' प्रदान किए

पीपीवीएफआरए अधिनियम की रजत जयंती और प्राधिकरण के 21वें स्थापना दिवस पर पुरस्कार समारोह का आयोजन हुआ

विलुप्त हो रहे बीजों के संरक्षण की दिशा में पीपीवीएफआरए अधिनियम की भूमिका महत्वपूर्ण- श्री चौहान

किसानों को पीपीवीएफआरए अधिनियम के बारे में और अधिक जागरुक किया जाना चाहिए- श्री शिवराज सिंह

बीजों की नई किस्म जरूरी लेकिन पुराने बीजों की किस्मों को भी बचाना होगा; केंद्रीय कृषि मंत्री

पीपीवीएफआरए अधिनियम में सुझावों को शामिल करते हुए संशोधन भी किया जाएगा- श्री चौहान

(एजेंसी)।

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली के पूसा कैंपस स्थित सी. सुब्रमण्यम सभागार में 'पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह और पीपीवीएफआरए अधिनियम, 2001 के रजत जयंती व पीपीवीएफआरए (पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण) के 21वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भागीदारी की और चयनिय किसान भाई-बहनों को पुरस्कृत किया।

इस अवसर केंद्रीय मंत्री ने तेलंगाना के कम्यूनिटि सीड बैंक, पूर्व वर्धमान पश्चिम बंगाल के शिक्षा निकेतन, मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ, असम के सीआरएस-एनए दिहिंग तेंगा उन्नयन समिति, उत्तराखंड के श्री भूपेंद्र जोशी, केरल के श्री टी. जोसेफ, श्री लक्षण प्रमाणिक, श्री अनंतमूर्ति जे, बिहार के श्री नकुल सिंह, उत्तराखंड के श्री नरेंद्र सिंह सहित विभिन्न अनेक श्रेणियों में किसान भाई-बहनों को पुरस्कार प्रदान किए गए।

कृषि मंत्री श्री चौहान ने संबोधित करते हुए कहा कि पीपीवीएफआरए प्राधिकरण ने पिछले 20 वर्षों में अद्भुत काम किया है। उन्होंने कहा कि भारतीय कृषि पद्धति अत्यंत प्राचीन है। कृषि हमारे देश का मूल रहा है। अनेक बीजों की किस्में पोषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन बीते वर्षों में कुछ किस्में विलुप्त होने की कगार पर आ गई थीं, जिन्हें सहेजने में किसान भाई-बहनों ने प्रशंसनीय भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि अधिनियम के माध्यम से बीज संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने 15 लाख रुपये तक की धनराशि देने का प्रावधान किया है। श्री चौहान ने कहा कि बीज सबसे बड़ी पूंजी है। बीज हमारा मौलिक अधिकार है। नई किस्मों को बढ़ावा देना जरूरी लेकिन पुरानी किस्मों को भी बचाना है, दोनों के बीच संतुलन बेहद जरूरी है।

केंद्रीय मंत्री ने पीपीवीएफआरए अधिनियम में नए सुझावों को शामिल करने के प्रस्ताव की भी चर्चा की और कहा कि जहां आवश्यक होगा वहां अधिनियम में नए सुझावों को शामिल करते हुए संशोधन किया जाएगा।

आगे, केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधिनियम के बारे में अभी भी किसानों को कम जानकारी है पंजीकरण को लेकर भी कुछ जटिलताएं हैं जिन्हें दूर किया जाना जरूरी है। पारदर्शिता के स्तर पर भी कुछ और कदम उठाए जाने चाहिए।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों तक अधिनियम का वास्तविक लाभ का हिस्सा भी सीमित रूप से ही पहुंच पाता है जिस दिशा में और अधिक प्रयास करने होंगे। केंद्रीय मंत्री ने पीपीवीएफआरए अधिनियम का अन्य कानूनों के साथ समन्वय और वैज्ञानिक डेटाबेस को मजबूत करने की भी बात कही।

केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक दृष्टि से किसानों के द्वारा पौधों और बीजों की किस्मों को संरक्षित करने के उपायों की चर्चा की और बताया कि इसी संरक्षण को आगे बढ़ाते हुए पीपीवीएफआरए के माध्यम से कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सशक्त प्रणाली पौधों और बीजों के संरक्षण में और अधिक उल्लेखनीय भूमिका निभाते हुए किसान कल्याण में नए अध्याय जोड़ेगी।

कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने मडुआ जैसी विभिन्न प्रजातियों के बीजों के संरक्षण पर बल देते हुए संगठन से इस दिशा में और सक्रिय प्रयास करने का आ'ान किया। उन्होंने मडुआ के समान अन्य पौधों की प्रजातियों के औषधीय महत्व को भी रेखांकित किया।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, केंद्रीय राज्य कृषि मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री देवेश चतुर्वेदी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉ. मांगी लाल जाट, कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव अजीत कुमार साहू, पीपीवीएफआरए के अध्यक्ष डॉ. त्रिलोचन महापात्रा, पीपीवीएफआरए के रजिस्ट्रार-जनरल डॉ. डी. के. अग्रवाल उपस्थित रहे।

पृष्ठभूमिः

पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना पौध किस्म एवं कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। इस प्राधिकरण का उद्देश्य नई पौध किस्मों के प्रजनकों को उनके नवाचार के लिए अधिकार प्रदान करना तथा किसानों के पारंपरिक ज्ञान और योगदान की रक्षा करना है। यह प्राधिकरण नई पौध किस्मों का पंजीकरण करता है, किसानों और समुदायों को उनके संरक्षण कार्य हेतु पुरस्कृत करता है तथा राष्ट्रीय पौध किस्म अभिलेख (ठं३ड्ढल्लं' फ्रॅ२३ी१ ड्ढ ढ'ल्ल३ १ं३ी३ी२) का संधारण करता है। साथ ही यह किसानों को बीज बचाने, बोने और पुनः उपयोग करने का अधिकार भी सुनिश्चित करता है, जिससे अनुसंधान, नवाचार और कृषि जैव विविधता को बढ़ावा मिलता है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की भूटान की राजकीय यात्रा पर संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति

(एजेंसी)।

भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 11-12 नवंबर 2025 तक भूटान की दो दिवसीय राजकीय यात्रा की।

यात्रा के दौरान, प्रधानमंत्री मोदी 11 नवंबर 2025 को चांगलिमथांग में महामहिम चतुर्थ ड्रुक ग्यालपो की 70वीं जयंती के अवसर पर भूटान के लोगों के साथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्पू में जारी वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भी भाग लिया। भूटान नरेश ने महोत्सव के दौरान सार्वजनिक पूजा-अर्चना के लिए थिम्पू में भारत से भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की उपस्थिति की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने महामहिम नरेश और महामहिम चतुर्थ ड्रुक ग्यालपो के साथ उपस्थित जनसमूह से भेंट करते हुए और भूटान के प्रधानमंत्री दाशो छेरिंग तोबगे के साथ वातार्लाप किया।

महामहिम नरेश ने 10 नवंबर को दिल्ली में हुए विस्फोट में हुई अनमोल जान-माल की दुखद क्षति पर भूटान की शाही सरकार और जनता की ओर से हार्दिक संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। भारत ने भूटान के समर्थन और एकजुटता के संदेश के प्रति आभार जताया।

प्रधानमंत्री मोदी ने आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम सहित भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के प्रति भारत के निरन्ॅ तर समर्थन की पुष्टि की और भूटान को उसकी प्रमुख विकास प्राथमिकताओं को हासिल करने और सभी क्षेत्रों में सतत विकास को आगे बढ़ाने में सक्रिय रूप से सहायता करने की भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। भूटानी प्रतिनिधिमंडल ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान भूटान में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न परियोजनाओं और देश के विकास में उनके योगदान के लिए भारत की सराहना की।

प्रधानमंत्री मोदी ने गेलेफू माइंडफुलनेस सिटी के लिए महामहिम के विजन को साकार करने के लिए भारत सरकार का पूर्ण समर्थन व्यक्त किया। उन्होंने गेलेफू में निवेशकों और आगंतुकों की सुगम आवाजाही के लिए असम के हतिसार में एक आव्रजन जांच चौकी स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की। महामहिम ने ग्यालसुंग अकादमियों के निर्माण के लिए भारत सरकार के सहयोग की सराहना की।

महामहिम नरेश और प्रधानमंत्री मोदी ने 11 नवंबर 2025 को भगवान बुद्ध के पवित्र पिपराहवा अवशेषों की गरिमामय उपस्थिति में, 1020 मेगावाट की पुनात्सांगछू-क्क जलविद्युत परियोजना का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। यह परियोजना जलविद्युत के क्षेत्र में भूटान और भारत के बीच मैत्री और अनुकरणीय सहयोग का प्रमाण है। उन्होंने पुनात्सांगछू-क्क से भारत को बिजली के निर्यात की शुरूआत का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने मार्च 2024 की ऊर्जा साझेदारी पर संयुक्त दृष्टिकोण के कार्यान्वयन पर भी संतोष व्यक्त किया।

दोनों नेताओं ने 1200 मेगावाट की पुनात्सांगछू-क जलविद्युत परियोजना के मुख्य बांध ढांचे पर कार्य फिर से शुरू करने के संबंध में बनी सहमति का स्वागत किया और परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए कार्य करने पर सहमति व्यक्त की। पुनात्सांगछू-क जलविद्युत परियोजना का कार्य पूर्ण होने पर यह दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना होगी।

उन्होंने भूटान में जलविद्युत परियोजनाओं में भारतीय कंपनियों की सक्रिय भागीदारी का स्वागत किया। भूटानी पक्ष ने भूटान में ऊर्जा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार द्वारा 40 अरब रुपये के रियायती ऋण सहायता की घोषणा की सराहना की।

दोनों पक्षों ने एकीकृत चेक पोस्टों की स्थापना सहित सीमा पार संपर्क में सुधार और सीमावर्ती बुनियादी ढांचे के विस्तार के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने नवंबर 2024 में दर्रांगा में आव्रजन जांच चौकी और मार्च 2025 में जोगीगोफा में अंतदेर्शीय जलमार्ग टर्मिनल और मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क के संचालन का स्वागत किया। दोनों पक्षों ने सितंबर 2025 में सीमा पार रेल संपर्क (गेलेफू-कोकराझार और समत्से-बानरहाट) की स्थापना पर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए परियोजना संचालन समिति की स्थापना का भी स्वागत किया।

भूटानी पक्ष ने भूटान को आवश्यक वस्तुओं और उर्वरकों की निर्बाध आपूर्ति के लिए संस्थागत व्यवस्था बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की। दोनों पक्षों ने नई व्यवस्था के अंतर्गत भारत से उर्वरकों की पहली खेप के आगमन का स्वागत किया।

दोनों पक्षों ने एसटीईएम, फिनटेक और अंतरिक्ष के नए क्षेत्रों में बढ़ते सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने यूपीआई के दूसरे चरण पर जारी कार्य का स्वागत किया, जो भारत आने वाले भूटानी आगंतुकों को क्यूआर कोड स्कैन करके स्थानीय मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करते हुए भुगतान करने में सक्षम बनाएगा। उन्होंने अंतरिक्ष सहयोग पर संयुक्त कार्य योजना के कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया। दोनों पक्षों ने भूटान में एसटीईएम शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाने में भारतीय शिक्षकों और नर्सों के अमूल्य योगदान को भी स्वीकार किया।

प्रधानमंत्री ने भूटान के चौथे नरेश से भेंट की और वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में भाग लिया

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज थिम्पू में भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंग्ये वांगचुक से भेंट की।

प्रधानमंत्री ने चौथे नरेश की 70वीं जयंती के अवसर पर बधाई दी और भारत सरकार एवं देश के नागरिकों की ओर से महामहिम नरेश के उत्तम स्वास्थ्य एवं कुशलता के लिए प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने भारत-भूटान मैत्री को और सुदृढ़ बनाने में उनके नेतृत्व, परामर्श और मार्गदर्शन के लिए चौथे नरेश का धन्यवाद किया। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा की। इस संदर्भ में, उन्होंने साझा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक बंधनों को रेखांकित किया जो दोनों देशों के लोगों को करीब लाते हैं।

प्रधानमंत्री मोदी थिम्पू में जारी वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के एक भाग के रूप में चांगलिमथांग स्टेडियम में कालचक्र दीक्षा समारोह में भूटान नरेश, भूटान के चौथे नरेश और भूटान के प्रधानमंत्री के साथ शामिल हुए। इस प्रार्थना की अध्यक्षता भूटान के मुख्य मठाधीश परम पावन जे खेंपो ने की।

कैबिनेट ने निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) को मंजूरी दी

20, 20,000 करोड़ रुपये तक की संपार्श्विक-मुक्त ऋण सहायता की परिकल्पना

एनसीजीटीसी के माध्यम से 100 प्रतिशत ऋण गारंटी

एमएसएमई और गैर-एमएसएमई दोनों निर्यातकों को लाभ

सीजीएसई से तरलता, बाजार विविधीकरण, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी

(एजेंसी)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना (सीजीएसई) शुरू करने को मंजूरी दे दी। इससे राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) को 100 प्रतिशत ऋण गारंटी कवरेज प्रदान किया जा सकेगा ताकि पात्र निर्यातकों, जिनमें एमएसएमई भी शामिल हैं, को 20,000 करोड़ रुपये तक की अतिरिक्त ऋण सुविधाएं प्रदान की जा सके।

कार्यान्वयन रणनीति और लक्ष्यः

इस योजना का कार्यान्वयन वित्तीय सेवा विभाग (डीएफएस) राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (एनसीजीटीसी) के माध्यम से करेगा ताकि एमएसएमई सहित पात्र निर्यातकों को एमएलआई अतिरिक्त ऋण सहायता प्रदान कर सके। डीएफएस सचिव की अध्यक्षता में गठित एक प्रबंधन समिति इस योजना की प्रगति और कार्यान्वयन की देखरेख करेगी।

प्रमुख प्रभावः

इस योजना से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के बढ़ने और नए एवं उभरते बाजारों में विविधीकरण को मदद मिलने की उम्मीद है। सीजीएसई के तहत संपार्श्विक-मुक्त ऋण को सुलभ करके, यह योजना तरलता को मजबूत करेगी, सुचारू व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करेगी और 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर के निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत की प्रगति को सुदृढ़ करेगी। इससे आत्मनिर्भर भारत की ओर देश की यात्रा को और मजबूती मिलेगी।

पृष्ठभूमिः निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जो वित्त वर्ष 2024-25 में सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 21 प्रतिशत रहा। विदेशी मुद्रा भंडार में निर्यात का महत्वपूर्ण योगदान होता है। नियातीन्मुखी उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 45 मिलियन से अधिक लोगों को रोजगार देते हैं और एमएसएमई कुल निर्यात में लगभग 45 प्रतिशत का योगदान करते हैं। निरंतर निर्यात वृद्धि भारत के चालू खाता संतुलन और व्यापक आर्थिक स्थिरता को बनाए रखने में सहायक रही है।

निर्यातकों को अपने बाजारों में विविधता लाने और भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उन्हें बेहतर वित्तीय सहायता और पर्याप्त समय प्रदान करना महत्वपूर्ण है। तदनुसार, अतिरिक्त तरलता सहायता प्रदान करने के लिए सक्रिय सरकारी योजना से व्यावसायिक वृद्धि सुनिश्चित होगी और बाजारों का विस्तार भी संभव होगा।

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को है ये गंभीर बीमारी, कैसे आईसीयू तक पहुंचे एक्टर? जानें 'ही-मैन' की तबीयत बिगड़ने का पूरा सच

(एजेंसी)।

बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को आखिरकार अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। 89 वर्षीय अभिनेता को कुछ दिनों पहले मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह डॉक्टरों की निगरानी में थे।

धर्मेंद्र की तबीयत में हुआ सुधार

अब डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि धर्मेंद्र की तबीयत में सुधार हुआ है और उन्हें गत 12 नवंबर2025 (बुधवार) सुबह करीब साढ़े सात बजे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है।

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल और बॉबी देओल ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर ये फैसला लिया है कि अब उनके पिता का इलाज और रिकवरी घर पर ही जारी रहेगी।

कैसे बिगड़ गई थी धर्मेंद्र की हालत?

-मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि एक्टर धर्मेंद्र की हालत पिछले कुछ दिनों से काफी नाजुक बनी हुई थी। उन्हें सांस फूलने की शिकायत के चलते मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं गत 11 नवंबर 2025 (मंगलवार) को एक्टर के अस्पताल में ही निधन की बात सामने आने लगी थी।

-वहीं एक्टर के निधन की बात सामने आते ही बेटी ईशा देओल ने साफतौर पर इस बात का खंडन किया था। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा था कि उनके पिता धर्मेंद्र की मौत नहीं हुई है। वह अस्पताल में हैं और उनकी हालत स्थिर है। वहीं एक्टर की पत्नी हेमा मालिनी ने भी मौत की बात को झूठा बताया था।

हेमा मालिनी तो इस तरह की फर्जी खबर फैलाने वालों को सरेआम लताड़ने भी लगी थीं। जानकारी के अनुसार गत 10 नवंबर 2025 को धर्मेंद्र की तबीयत अचानक काफी बिगड़ गई थी। उन्हें आईसीयू से वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था। इसके अलावा धर्मेंद्र के परिवार वालों के अलावा कई बड़े सेलेब्स जैसे शाहरुख खान सलमान खान, लिजेंड्री एक्टर से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे थे।

-आपको बता दें कि ब्रीच कैंडी अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि 89 साल के धर्मेंद्र को सांस फूलने की शिकायत के चलते एडमिट कराया गया था। पहले उन्हें आईसीयू में रखा गया था लेकिन बाद में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया था।

-अस्पताल की तरफ से बताया गया था कि जब धर्मेंद्र हॉस्पिटल पहुंचे थे तो उन्हें सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। हालांकि उम्र अधिक होने पर ऐसा होना सामान्य है। डॉक्टरों की तरफ से बताया गया है कि धर्मेंद्र को फेफड़ों में परेशानी हो रही थी। ऐसे में उन्हें पिछले कुछ समय से सांस लेने में दिक्कत भी हो रही थी।

क्या होता है डिस्पनिया

-आमतौर पर उम्र बढ़ने के साथ साथ लोगों में सांस संबंधी समस्याएं बढ़ती रहती हैं। सांस लेने में तकलीफ होने वाली बीमारी को डिस्पनिया या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ कहते हैं। ये एक लक्षण है जिसका मतलब है सांस लेने में असुविधा या सांस न ले पाना और ये कई अलग-अलग बीमारियों का संकेत हो सकता है।

-दिल और फेफड़ों की बीमारियां डिस्पेनिया के सामान्य कारण हैं। डिस्पनिया, जिसे आम भाषा में सांस फूलना या सांस लेने में तकलीफ कहते हैं, सांस लेने में असहजता या कठिनाई की व्यक्तिपरक अनुभूति है। यह अक्सर हृदय या फेफड़ों की समस्याओं का लक्षण होता है, लेकिन यह अस्थमा, निमोनिया, एनीमिया, चिंता या शारीरिक परिश्रम के कारण भी हो सकता है।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 25,060 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ भारत के निर्यात इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी

(एजेंसी)।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धा - विशेष रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम-प्रधान सेक्टरों को - सुदृढ़ बनाने के लिए केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक प्रमुख पहल निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दे दी है।

यह मिशन वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 के लिए 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ निर्यात संवर्धन के लिए एक व्यापक, लचीला और डिजिटल रूप से संचालित संरचना प्रदान करेगा। ईपीएम कई खंडित योजनाओं से एक एकल, परिणाम-आधारित और अनुकूलनीय तंत्र की ओर कार्यनीतिक बदलाव का प्रतीक है, जो वैश्विक व्यापार चुनौतियों और निर्यातकों की उभरती आवश्यकताओं का त्वरित प्रत्युत्तर हो सकता है।

ईपीएम एक सहयोगात्मक ढांचे पर आधारित है जिसमें वाणिज्य विभाग, एमएसएमई मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वित्तीय संस्थानों, निर्यात संवर्धन परिषदों, वस्तु बोर्डों, उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित अन्य प्रमुख हितधारक शामिल हैं।

यह मिशन दो एकीकृत उप-योजनाओं के माध्यम से प्रचालित होगाः

निर्यात प्रोत्साहन - ब्याज अनुदान, निर्यात लेनदारी लेखा क्रय (फैक्टरिंग), संपार्श्विक गारंटी, ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए क्रेडिट कार्ड और नए बाजारों में विविधीकरण के लिए ऋण वृद्धि सहायता जैसे कई साधनों के माध्यम से एमएसएमई के लिए किफायती व्यापार वित्त तक पहुंच में सुधार पर केंद्रित है।

निर्यात दिशा - गैर-वित्तीय सक्षमताओं पर केंद्रित है जो बाजार की तैयारी और प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाती हैं। इसमें निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडिंग, पैकेजिंग के लिए सहायता और व्यापार मेलों में भागीदारी, निर्यात भंडारण और लॉजिस्टिक्स, अंतदेर्शीय परिवहन प्रतिपूर्ति और व्यापार खुफिया और क्षमता निर्माण पहलें शामिल हैं।

ईपीएम प्रमुख निर्यात सहायता योजनाओं जैसे कि ब्याज समकरण योजना (आईईएस) और बाजार पहुंच पहल (एमएआई) को समेकित करता है और उन्हें समकालीन व्यापार आवश्यकताओं के साथ संयोजित करता है।

यह मिशन उन संरचनात्मक चुनौतियों का प्रत्यक्ष रूप से समाधान करने के लिए डिजाइन किया गया है जो भारतीय निर्यात को बाधित करती हैं। इनमें शामिल हैं:

सीमित और महंगी व्यापार वित्त पहुंच,

अंतर्राष्ट्रीय निर्यात मानकों के साथ अनुपालन की उच्च लागत,

अपर्याप्त निर्यात ब्रांडिंग और खंडित बाजार पहुंच और

आंतरिक और कम निर्यात-तीव्रता वाले क्षेत्रों में निर्यातकों के लिए लॉजिस्टिक्स संबंधी हानि।

ईपीएम के तहत, हाल ही में वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित सेक्टरों जैसे कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों को प्राथमिकता सहायता प्रदान की जाएगी। ये युक्तियां निर्यात ऑर्डरों को बनाए रखने, रोजगारों की रक्षा करने और नए भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को बढ़ावा देने में मदद करेंगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें आवेदन से लेकर वितरण तक सभी प्रक्रियाओं का प्रबंधन विद्यमान व्यापार प्रणालियों के साथ एकीकृत एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा।

RNI No.: UPHIN/25/A1697 Published & Owned by AJAYKUMAR RAMANLAL PRAJAPATI and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh. and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : ASHWANI KUMAR

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नर्सिंग शिक्षा और पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय परामर्श और अनुभव-साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया

नर्स और दाइयां भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का आधार और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं: केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव

भारत की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का श्रेय उसके नर्सिंग कार्यबल की शक्ति और प्रतिबद्धता को जाता है: वीके पॉल, सदस्य, नीति आयोग

भारत वैश्विक नर्सिंग कार्यबल में दुनिया के सबसे बड़े योगदानकताओं में से एक के रूप में उभरा है: भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधि

(एजेंसी)।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) और जेएचपीईजीओ के सहयोग से भारत में नर्सिंग नीति प्राथमिकताओं और सर्वोत्तम प्रथाओं पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श और अनुभव साझाकरण कार्यशाला का आयोजन किया। इसका उद्देश्य नीतिगत संवाद को मजबूत करना और नर्सिंग तथा मिडवाइफरी क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाना है।

कार्यशाला में देश भर के नीति निमार्ताओं, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, नियामकों, नर्सिंग शिक्षकों, पेशेवर संघों और विकास भागीदारों सहित प्रमुख हितधारकों को

एक मंच पर लाया गया। इस परामर्श का उद्देश्य वर्तमान में जारी पहलों की समीक्षा करना, उभरती चुनौतियों की पहचान करना और भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की प्राथमिकताओं और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के अनुरूप नर्सिंग प्रशासन, शिक्षा और कार्यबल प्रबंधन को मजबूत करने के लिए नवीन मॉडलों को साझा करना था।

उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने कहा कि नर्सें और दाइयाँ भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली का आधार और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों में से एक हैं। उन्होंने बल देते हुए कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर और आशा कार्यकताओं के साथ मिलकर, वे सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (यूएचसी) प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

उन्होंने कहा कि भारत के हालिया सुधार, जिनमें राष्ट्रीय नर्सिंग एवं मिडवाइफरी आयोग (एनएनएमसी) की स्थापना, योग्यता-आधारित पाठ्यक्रम को अपनाना और नियामक ढांचे को आधुनिक बनाने की पहल शामिल हैं, नर्सिंग पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में प्रमुख उपलब्धि हैं।

उन्होंने कहा कि इस कार्यशाला के दौरान प्रत्येक राज्य से उभर कर आने वाली सर्वोत्तम प्रथाओं को राष्ट्रीय नीति निर्माण के लिए मार्गदर्शक सुझावों के रूप में कार्य करना चाहिए तथा अन्य राज्यों को देश भर में नर्सिंग क्षेत्र में व्यापक अनुकरण और सुधार के लिए इन मॉडलों पर ध्यान देना चाहिए।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में नीति आयोग के स्वास्थ्य सदस्य, प्रोफेसर वी. के. पॉल ने इस महत्वपूर्ण परामर्श के आयोजन के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन की सराहना की। भारत की स्वास्थ्य प्रणाली को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जिसका मुख्य कारण इसके नर्सिंग कार्यबल की क्षमता और समर्पण है। उन्होंने दोहराया कि नर्सिंग भारत की व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रणाली की रीढ़ है।

नर्सों के प्रशिक्षण की गुणवत्ता पर चिंता व्यक्त करते हुए, डॉ. पॉल ने कहा कि यह अभी भी ध्यान देने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र बना हुआ है। उन्होंने नर्सिंग शिक्षा में सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया और देखभाल एवं पेशेवर उत्कृष्टता के उच्च मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन पर अधिक जोर देने का आ'ान किया।

इस अवसर पर अपने सम्बोधन में भारत में विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रतिनिधि डॉ. पेडेन ने नर्सिंग और मिडवाइफरी क्षेत्र में देश की उल्लेखनीय प्रगति की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक नर्सिंग कार्यबल में दुनिया के सबसे बड़े योगदानकताओं में से एक के रूप में उभरा है।

फियो ने निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) और निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना को कैबिनेट की मंजूरी का स्वागत किया: यह भारत के निर्यात इकोसिस्टम के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव है

नई दिल्ली, 12 नवंबर, 2025: फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनाइजेशन (फियो) केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को मंजूरी दिए जाने का स्वागत करता है। यह केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य विशेष रूप से एमएसएमई, पहली बार निर्यात करने वाले और श्रम-प्रधान सेक्टरों के लिए भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करना है। वित्त वर्ष 2025-26 से वित्त वर्ष 2030-31 तक 25,060 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाला यह मिशन, कई निर्यात संवर्धन योजनाओं को एक व्यापक, परिणाम-आधारित और डिजिटल रूप से संचालित ढाँचे में समेकित करके एक बड़े संरचनात्मक सुधार का प्रतीक है।

इस घटनाक्रम पर बोलते हुए फियो के अध्यक्ष श्री एस. सी. रल्हन ने कहा, "निर्यात संवर्धन मिशन भारत के व्यापार क्षेत्र के लिए एक व्यावहारिक और दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाता है। वित्तीय और गैर-वित्तीय युक्तियों को एक एकीकृत ढाँचे के अंतर्गत लाकर, यह मिशन वैश्विक व्यापार गतिशीलता के लिए आवश्यक निरंतरता, लचीलापन और जवाबदेही प्रदान करता है। यह विशेष रूप से एमएसएमई को सशक्त बनाएगा, जिन्हें अक्सर किफायती वित्त और अनुपालन सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती है।"

मिशन की समावेशिता पर प्रकाश डालते हुए, श्री रल्हन ने कहा, "ईपीएम उन संरचनात्मक चुनौतियों - वित्त तक सीमित पहुँच और उच्च अनुपालन लागत से लेकर कमजोर ब्रांडिंग और लॉजिस्टिक्स बाधाओं तक- का समयोचित समाधान है, जिन्होंने लंबे समय से भारतीय निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को कुंद किया है। इन मुद्दों से सीधे निपटकर, यह पहल निर्यात की गति को बनाए रखने, रोजगार की रक्षा करने और भारत के निर्यात आधार को नए भौगोलिक क्षेत्रों और उभरते सेक्टरों में विविधता प्रदान करने में मदद करेगी।"

ईपीएम के तहत, कपड़ा, चमड़ा, रत्न एवं आभूषण, इंजीनियरिंग सामान और समुद्री उत्पादों जैसे हालिया वैश्विक टैरिफ वृद्धि से प्रभावित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, जिससे निरंतर निर्यात ऑर्डर और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जो पारदर्शिता, गति और सुगम पहुँच सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी प्रक्रियाओं का डिजिटल प्रबंधन करेगा।

श्री रल्हन ने कहा, "मौजूदा व्यापार प्रणालियों के साथ मिशन का डिजिटल एकीकरण निर्यातकों के अनुभव को बदल देगा - कागजी कार्रवाई को कम करेगा, समन्वय में सुधार करेगा और समय पर वितरण सुनिश्चित करेगा। यह विकसित भारत @2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप एक स्मार्ट, तकनीक-सक्षम निर्यात इकोसिस्टम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"

फियो अध्यक्ष ने इस बात पर जोर दिया कि निर्यात संवर्धन मिशन न केवल निर्यात में एमएसएमई की भागीदारी को बढ़ावा देगा, बल्कि विनिर्माण, लॉजिस्टिक्स और संबद्ध सेवाओं में रोजगार सृजन को भी उत्प्रेरित करेगा, जिससे वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति मजबूत होगी।

फियो अध्यक्ष ने कहा कि निर्यातकों के लिए ऋण गारंटी योजना न केवल को-लैटेरल ऋण प्रदान करेगी, बल्कि अतिरिक्त वित्तीय तरलता भी प्रदान करेगी, जो समय की मांग है।

श्री रल्हन ने कहा 'फियो मिशन के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए वाणिज्य विभाग, डीजीएफटी इकोसिस्टम और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर है। यह भारतीय निर्यात के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण है और हमें इसे पूरी प्रतिबद्धता के साथ ग्रहण करना चाहिए।'

कोयला मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक

(एजेंसी)।

कोयला मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक आज दिनांक 12 नवंबर, 2025 को अशोक होटल, नई दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता माननीय कोयला एवं खान मंत्री श्री जी. किशन रेड्डी जी ने की। बैठक में माननीय सांसदगण, अन्य सदस्यगण, सचिव (कोयला) तथा कोयला मंत्रालय के उच्च अधिकारीगण, राजभाषा विभाग के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

माननीय कोयला एवं खान मंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं है बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक धरोहर, राष्ट्रीय एकता और जन-मन को जोड़ने का माध्यम है। हिंदी भाषा की सरलता और सहजता अभिव्यक्ति को सार्थकता प्रदान करती है। आज विश्व स्तर पर हिंदी की स्वीकार्यता बढ़ी है। आज

हिंदी को यूएन की आधिकारिक भाषा बनाने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित राजभाषा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों में समुचित प्रयास किए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी ने विशेष रूप से यह भी उल्लेख किया कि माननीय सदस्यों से जो बहुमूल्य सुझाव प्राप्त हुए हैं, कोयला मंत्रालय द्वारा उन पर अमल किया जाएगा।

उक्त बैठक में पीपीटी के माध्यम से कोयला मंत्रालय और इसके नियंत्रणाधीन कार्यालयों द्वारा राजभाषा के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों को भी दर्शाया गया। इसके अलावा, राजभाषा के प्रति 'निष्ठा की प्रतिष्ठा' हेतु माननीय कोयला एवं खान मंत्री जी द्वारा कंपनी प्रमुखों एवं राजभाषा अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। इस बैठक में माननीय कोयला एवं खान मंत्री जी द्वारा राजभाषा विभाग की स्थापना की स्वर्ण जयंती के अवसर को समर्पित, कोयला मंत्रालय की प्रथम पत्रिका 'अभिव्यक्ति', का भी विमोचन किया गया। मंत्रालय समिति के माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर अमल करने का पूर्ण प्रयास करेगा।

डीडीडब्ल्यूएस ने जल जीवन मिशन के तहत 'जनभागीदारी के लिए संचार और पीआरए टूल्स ' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने कार्यशाला को संबोधित किया और कई प्रमुख पहलों का शुभारंभ किया

ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं की स्थिरता के लिए सहभागी टूल्स के सह-निर्माण में आरडब्ल्यूपीएफ साझीदारों और राज्यों की सक्रिय भागीदारी

(एजेंसी)।

जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग (डीडीडब्ल्यूएस) ने 12 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के स्कोप कॉम्प्लेक्स में 'सामुदायिक सहभागिता (जनभागीदारी) को बढ़ावा देने के लिए संचार और पीआरए टूल्स' पर ग्रामीण वाश पार्टनर्स फोरम (आरडब्ल्यूपीएफ) की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सीआर पाटिल, डीडीडब्ल्यूएस के सचिव श्री अशोक के.के. मीणा, राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एनजेजेएम) के अपर सचिव एवं मिशन निदेशक श्री कमल किशोर सोन, एनजेजेएम की संयुक्त सचिव श्रीमती स्वाति मीणा नाइक, स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक श्रीमती ऐश्वर्या सिंह, डीडीडब्ल्यूएस, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(एमओएएफडब्ल्यू), जल संसाधन विभाग, राष्ट्रीय जल मिशन, पंचायती राज मंत्रालय, केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीडब्ल्यूजीबी), भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी), राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र (एनडब्ल्यूआईसी), भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बीआईएसएजी-एन) और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (एनआरएससी) के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, आरडब्ल्यूपीएफ के सदस्य और विकास साझीदार भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

कार्यशाला की शुरूआत केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में प्रमुख पहलों के अनावरण के साथ हुई। इनमें शामिल हैं:

स्रोत स्थिरता के लिए निर्णय समर्थन प्रणाली (डीएसएस) जेजेएम पंचायत डैशबोर्ड

सामुदायिक रेडियो कार्यक्रम की पहली कड़ी - "स्वच्छ सुजल गांव की कहानीः रेडियो की जुबानी"

ग्रामीण भारत में समुदाय-प्रबंधित पाइप जल प्रणालियों पर लघु पुस्तिका - "जन भागीदारी से हर घर जल"

केंद्रीय मंत्री ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) और जल जीवन मिशन प्रधानमंत्री के इस विजन के जीवंत प्रतीक हैं कि "जन भागीदारी से ही जन कल्याण संभव है।" उन्होंने रेखांकित किया कि 9 करोड़ से अधिक महिलाओं को पानी लाने के झंझट से मुक्ति मिल गई है और विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार, ग्रामीण भारत प्रतिदिन 5.5 करोड़ व्यक्ति-घंटे बचा सकता है, जिससे उत्पादकता बढ़ेगी और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई "जल संचय जन भागीदारी" पहल दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए भूजल पुनर्भरण, वर्षा जल संचयन और बोरवेल कायाकल्प पर केंद्रित है। श्री पाटिल ने डिजिटल नवाचार और पारदर्शिता के माध्यम से ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने और उन्हें जल संसाधनों के प्रबंधन में आत्मनिर्भर बनाने के चल रहे प्रयासों को रेखांकित किया।

अपने उद्घाटन भाषण में, पेयजल एवं स्वच्छता सचिव श्री अशोक के.के. मीणा ने इस बात पर बल दिया कि जनभागीदारी ही इस मिशन का मूल दर्शन है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन को सामुदायिक स्वामित्व, स्थानीय निर्णय प्रक्रिया और स्थिरता पर आधारित सर्वाधिक बुनियादी स्तर के कार्यक्रम के रूप में डिजाइन किया गया है। उन्होंने कहा, "लोग लाभार्थी नहीं हैं; वे अपनी जल प्रणालियों के संरक्षक हैं।"

सचिव ने संचार और व्यवहार परिवर्तन के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यशाला का उद्देश्य ऐसे टूल्स तैयार करना है जो भागीदारी को ठोस कार्रवाई में बदल सकें। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और पारदर्शिता, जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रगति के दो प्रमुख स्तंभ बन गए हैं।

क्यूसीआई और बीएचईएल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में संयुक्त रूप से अंतर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम गुणवत्ता मंथन का आयोजन गुणवत्ता और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए किया

(एजेंसी)।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के सहयोग से नई दिल्ली स्थित अपने मुख्यालय में अंतर पीएसयू गुणवता मंथन का आयोजन किया।

कार्यक्रम के दौरान हुई चचाओं में संरचित ढाँचों और उत्कृष्टता मॉडलों के माध्यम से राष्ट्रीय गुणवत्ता आंदोलन को आगे बढ़ाने में क्यूसीआई की भूमिका पर जोर दिया गया। भाग लेने वाले सार्वजनिक उपक्रमों ने सिक्स सिग्मा, लीन, क्वालिटी सर्कल्स, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस (टीपीएम), डिजिटल ऑटोमेशन और आपूर्तिकर्ता विकास कार्यक्रमों जैसे क्षेत्रों में अपने अनुभव और पहलों को साझा किया। इस संवादात्मक सत्र ने प्रथाओं के मानकीकरण और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद की।

इस पहल का उद्देश्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच सहयोग और पारस्परिक ज्ञान को मजबूत करना है, जो कि क्यूसीआई के वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी और गुणवत्ता-संचालित संस्थानों के विकास के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो विकसित भारत 2047 के उद्देश्यों में योगदान देगा।

बीएचईएल के कॉर्पोरेट गुणवत्ता एवं व्यावसायिक उत्कृष्टता प्रमुख डॉ. दुर्गेश सी. गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित इस कार्यक्रम में, राष्ट्रीय प्रमाणन

निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) - क्यूसीआई के सहयोग से, बीईएल, बीपीसीएल, ईआईएल, गेल, आईओसीएल, पीजीसीआईएल और टीएचडीसी सहित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) एक मंच पर आए। इस मंच ने गुणवत्ता प्रबंधन, व्यावसायिक उत्कृष्टता, परिचालन दक्षता, आपूर्ति श्रृंखला गुणवत्ता, डिजिटल परिवर्तन और स्थिरता-उन्मुख प्रदर्शन में सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान-प्रदान को सुगम बनाया।

क्यूसीआई के अध्यक्ष, श्री जैक्सय शाह ने कहा कि क्यूसीआई सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र सहित भारतीय उद्योग जगत में गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अंतर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम गुणवत्ता मंथन औद्योगिक परिचालनों में गुणवत्ता और उत्कृष्टता की संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में एक रचनात्मक कदम है।

बीएचईएल के निदेशक (अनुसंधान एवं विकास), श्री एस.एम. रामनाथन ने अपने मुख्य भाषण में भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास में सार्वजनिक उपक्रमों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने डिजाइन से लेकर वितरण तक सरलता और प्रभावशीलता की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि गुणवत्तापूर्ण परिणाम, बेहतर ग्राहक संतुष्टि और परिचालन दक्षता में बदल सकें।

एनएबीसीबी के अध्यक्ष डॉ. रवि पी. सिंह ने सभी उद्यमों में एक विश्वसनीय और सक्षम गुणवत्ता आश्वासन ढाँचे के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय गुणवत्ता प्रणालियों की विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए अनुरूपता मूल्यांकन तंत्र को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया।

कार्यक्रम का समापन क्यूसीआई और बीएचईएल के संयुक्त सत्र के साथ हुआ, जिसमें संस्थागत सहयोग के संभावित मॉडलों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई, जिसमें अनुकूलित गुणवत्ता साझेदारी और परिपक्वता संवर्धन कार्यक्रम शामिल थे। अंतर-सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम गुणवत्ता मंथन ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में गुणवत्ता-उन्मुख शासन और परिचालन उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए क्यूसीआई और बीएचईएल की प्रतिबद्धता की पुष्टि की।

राजस्व खुफिया निदेशालय ने 'ऑपरेशन बुलियन ब्लेज' के तहत मुंबई में सोने की तस्करी करके उसे पिघलाने वाले एक बड़े गिरोह का पदार्फाश किया; 11.88 किलोग्राम सोना जब्त किया गया और 11 लोग गिरफ्तार किए गए

(एजेंसी)।

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने "ऑपरेशन बुलियन ब्लेज" के तहत मुंबई में सोने की तस्करी, उसे गुप्त भट्टियों में पिघलाने और परिष्कृत सोने को अवैध रूप से ग्रे मार्केट में बेचने में शामिल एक संगठित गिरोह का पदार्फाश किया है।

डीआरआई अधिकारियों ने विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर, 10.11.2025 को मुंबई में चार गुप्त स्थानों पर सोने को पिघलाने वाली दो अवैध इकाइयों और सोने को अवैध रूप से ग्रे मार्केट में बेचने दो अपंजीकृत दुकानों की तलाशी ली।

दोनों अवैध भट्टियों में तस्करी किए गए सोने को मोम और अन्य रूपों में बदलने के लिए पूरी व्यवस्था थीं। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अवैध भट्टियां चलाने वालों को हिरासत में ले लिया और मौके पर ही 6.35 किलोग्राम सोना बरामद किया। इसके बाद, तस्करी का सोना और पिघली हुई छड़ें स्थानीय खरीदारों को बेचने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दो दुकानों की भी तलाशी ली गई, जिसमें से एक दुकान से 5.53

किलोग्राम अतिरिक्त सोने की छड़ें बरामद हुईं।

राजस्व खुफिया निदेशालय ने 15.05 करोड़ रुपये मूल्य का 11.88 किलोग्राम 24 कैरेट सोना और 13.17 लाख रुपये मूल्य की 8.72 किलोग्राम चांदी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत जब्त की।

सोने की तस्करी, गलाने और अवैध बिक्री में शामिल मास्टरमाइंड सहित कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह गिरोह मास्टरमाइंड द्वारा अपने पिता, एक प्रबंधक, सोना पिघलाने वाले चार व्यक्तियों, तस्करी किए गए सोने का रिकॉर्ड रखने वाले एक एकाउंटेंट और सोने के वितरण का काम संभालने वाले तीन डिलीवरी कर्मियों की मिलीभगत से चलाया जा रहा था। सभी आरोपियों को मुंबई के संयुक्त वित्तीय आयुक्त (जेएमएफसी) के समक्ष पेश किया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सोने की तस्करी और अवैध बिक्री के लिए एक सुनियोजित साजिश रची गई थी, जो देश की स्वर्ण आयात नीति का घोर उल्लंघन है और इसका उद्देश्य सरकारी राजस्व को हानि पहुंचाना था। डीआरआई राजस्व और बाजारों को नुकसान पहुंचाने वाले और राजकोषीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करने वाले उन सभी संगठित तस्करी नेटवर्कों को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। डीआरआई देश की आर्थिक और राजकोषीय स्थिरता की रक्षा करके निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यापारिक वातावरण सुनिश्चित करता है।

मामले की आगे की जांच जारी है।

रक्षा उत्पादन सचिव ने कहा - विघटनकारी तकनीकों से प्रेरित आधुनिक क्षमताओं और स्टार्ट-अप्स तथा नवप्रवर्तकों के साथ गहन सहयोग की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका

(एजेंसी)।

सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार ने देश की तकनीकी क्षमता को सशक्त बनाने और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए स्टार्ट-अप्स तथा नवप्रवर्तकों के साथ व्यापक सहयोग का आ'ान किया है। वे 12 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान द्वारा आयोजित दिल्ली रक्षा संवाद को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नए तकनीकी क्षेत्रों में प्रगति को गति देने और रक्षा प्रणालियों के तकनीकी आधार को सुदृढ़ करने के लिए युवा उद्यमियों तथा नवप्रवर्तकों के साथ साझेदारी के महत्व पर बल दिया।

सचिव (रक्षा उत्पादन) ने कहा कि आज की अत्याधुनिक क्षमताएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी विघटनकारी प्रौद्योगिकियों द्वारा संचालित हैं। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नवाचार की गति तेज करने और व्यवहारिक समाधान विकसित करने के लिए सभी हितधारकों के बीच विचारों एवं सूचनाओं का निर्बाध तथा प्रभावी आदान-प्रदान अत्यंत आवश्यक है।

संजीव कुमार ने आधुनिक युद्ध की तैयारियों में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की निर्णायक भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार (आईडीईएक्स) और प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) जैसी गतिविधियां नई पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों में नवाचार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य को प्राप्त करने में स्टार्ट-अप्स तथा एमएसएमई को सशक्त बनाया जा रहा है। इन सभी के माध्यम से भारत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में अपने मार्ग को और अधिक सुदृढ़ कर रहा है।

'रक्षा क्षमता विकास के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग' विषय पर आयोजित दिल्ली रक्षा संवाद में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों, सशस्त्र बलों के नेतृत्व, उद्योग प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने भाग लिया।

गजरौला-शिवनगर मार्ग की स्थिति जर्जर: दर्जनों गांवों के लोग परेशान, गड्ढों के कारण आवागमन में हो रही परेशानी

(एजेंसी)।

पीलीभीत के गजरौला से शिवनगर को जोड़ने वाला मार्ग पूरी तरह जर्जर हो चुका है। चार साल पहले बनी 7 किलोमीटर लंबी यह सड़क अब जगह-जगह गड्ढों और उखड़ी हुई सतह के कारण खंडहर में तब्दील हो गई है। स्थानीय ग्रामीण इसकी तत्काल मरम्मत की मांग कर रहे हैं।

इस मार्ग से स्कूल-कॉलेज के विद्यार्थी, किसान और दैनिक यात्री सबसे अधिक प्रभावित हैं। बरसात और कोहरे के मौसम में सड़क की स्थिति और खराब हो जाती है, जिससे आवागमन बेहद मुश्किल हो जाता है। इसके अतिरिक्त, जंगली जानवरों की आवाजाही के कारण हादसों का खतरा भी बढ़ गया है।

यह मार्ग बांनगज, शिवनगर, गांवों को जोड़ता है। ग्रामीणों का

बिधिपुर, लालपुर, बिहारीपुर, इटौरिया, महद खास और भुढ़िया सहित दर्जनों आरोप है कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया था, जिसके कारण यह इतनी जल्दी खराब हो गई।

ग्रामीणों ने सड़क की मरम्मत के लिए कई बार प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया है। उन्होंने बताया कि सांसद जितिन प्रसाद ने भी इस मार्ग के सुधार का मुद्दा उठाया था, लेकिन इसके बावजूद सड़क की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है।

बैजनागर के प्रधान रमेश ने जानकारी दी कि उन्होंने सड़क निर्माण की मांग को लेकर संबंधित अधिकारियों को लिखित शिकायत पत्र सौंपा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द सड़क की मरम्मत कराने की अपील की है ताकि उनकी परेशानियां कम हो सकें।

पीलीभीत पहुंचे भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह

(एजेंसी)।

पीलीभीत, 12 नवंबर: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष सिंह आज संगठनात्मक कार्यों की समीक्षा करने जिले में पहुंचे। उनका यह दौरा आगामी बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रमों को लेकर ज्यादा केंद्रित रहा। पार्टी के जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने बिरसा मुंडा के योगदान पर विस्तार से बात की, लेकिन स्थानीय स्तर की गुटबाजी, प्रशासनिक विवादों और अन्य राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठने पर चुप्पी साध ली। इस चुप्पी ने जिले में चल रही अटकलों को नई हवा दे दी है।

संतोष सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा नीति पर काम करती है और सभी महापुरुषों की जयंतियों को समान सम्मान के साथ मनाती है। यह उनकी राष्ट्रवादी विचारधारा का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने बिरसा मुंडा को भारतीय संस्कृति, स्वतंत्रता संग्राम और आदिवासी समाज के उत्थान का महान प्रतीक बताया। बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आदिवासियों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष किया, वह आज भी प्रेरणा स्रोत है। सिंह ने कहा, "पार्टी देशभर में उनकी जयंती पर बड़े स्तर के कार्यक्रम आयोजित करेगी। पीलीभीत जिले में विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लोगों के बीच जाकर ये कार्यक्रम मनाए जाएंगे।

हम उनके आदर्शों को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।"

उन्होंने जिले के कार्यकर्ताओं से भी अपील की कि वे इन कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करें। संगठनात्मक समीक्षा के दौरान उन्होंने स्थानीय इकाइयों की प्रगति पर चर्चा की और आगामी चुनावी तैयारियों को मजबूत करने पर जोर दिया। हालांकि, प्रेस वार्ता के दौरान स्थानीय मुद्दों पर सवालों की बौछार हो गई। जब पत्रकारों ने पीलीभीत की आंतरिक गुटबाजी के बारे में पूछा, तो सिंह ने स्पष्ट रूप से टालते हुए कहा कि उनका दौरा केवल संगठनात्मक है।

विशेष रूप से, ब्लॉक मरौरी की प्रमुख के वित्तीय अधिकारों को सीज किए जाने के गंभीर मामले पर सवाल उठा। इसके अलावा, जिले की राजनीति में चल रहे नगर पालिका अध्यक्ष और एक मंत्री के बीच तनाव की खबरें, तथा विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के संगठन मंत्री पर दर्ज हुए मुकदमे जैसे संवेदनशील विषयों पर भी सिंह ने जानकारी न होने की बात कही। उन्होंने हर सवाल पर अनभिज्ञता जताई और बयान देने से परहेज किया। एक पत्रकार के सवाल पर उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, "ये स्थानीय मुद्दे हैं, जिनकी जानकारी मुझे नहीं है। हमारा फोकस संगठन और राष्ट्रीय मुद्दों पर है।"

स्थानीय कार्यकताओं के बीच इस चुप्पी को लेकर चचाएं तेज हो गईं। कुछ का मानना है कि प्रदेश नेतृत्व जिले की इन आंतरिक कलहों से दूरी बनाए रखना चाहता है, ताकि पार्टी की एकजुट छवि बनी रहे। वहीं, विपक्षी दलों ने इसे भाजपा की कमजोरी बताया। संतोष सिंह का यह दौरा शाम तक चला, जिसमें उन्होंने कई स्थानीय नेताओं से बंद कमरे में बैठकें भी कीं।

कुल मिलाकर, बिरसा मुंडा जयंती के कार्यक्रमों पर दिया गया जोर सराहनीय रहा, लेकिन स्थानीय विवादों पर साधी चुप्पी ने सवालों को जन्म दे दिया। जिले में भाजपा की एकता पर अब और नजरें टिक गई हैं। राजनीति का यह नया ट्विस्ट क्या रंग लाएगा?

महिला थाना टीम ने मिशन शक्ति के तहत सागर इंटर कॉलेज में छात्राओं को किया जागरूक

(एजेंसी)।

बाराबंकी:- पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय के निदेर्शानुसार अपर पुलिस अधीक्षक (उत्तरी) विकास चंद्र त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में क्षेत्राधिकरी नगर संगम कुमार के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज 5 .0 महिला सशक्तिकरण अभियान,साइबर जागरूकता एवं यातायात जागरूकता अभियान के तहत महिला थानाध्यक्ष मुन्नी सिंह मिशन शक्ति टीम उ0नि0 कामिनी साहू म0हे0कां0 सुमन मौर्य म0हे0कां0 आशा यादव, म0कां0 आरती के द्वारा सागर इंटर कॉलेज बाराबंकी में नारी सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाकर छात्र-छात्राओं को नारी सुरक्षा सम्मान व स्वालंबन

हेतु -घरेलू हिंसा,बाल विवाह, पास्को एक्ट , गुड टच बैड टच व साइबर ¨क्राइम संबंधी अपराध महिला मिशन शक्ति केंद्र यातायात के नियमों बारे में जागरूक किया गया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये गये हेल्पलाइन नंबरों 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर,1090 वूमेन पावर हेल्पलाइन नंबर,1098 चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर,1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर,112 पुलिस आपातकालीन सेवा,108 एंबुलेंस सेवा,102 स्वास्थ्य सेवा के बारे में जानकारी दी गई व सरकार द्वारा चलाई गई लाभकारी योजनाओं जैसे- सामूहिक विवाह योजना, कन्या सुमंगला योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, आदि के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई व पंपलेट वितरित किया गया एवं उनकी समस्याएं पूछी गई।

विवाहिता ने पति-सास-ससुर पर मारपीट व घर से निकालने का आरोप - शराब व फोन विवाद से यातनाएं, कोतवाली में तहरीर, पुलिस जांच शुरू

(एजेंसी)।

पीलीभीत के दियोरिया कला गांव में एक विवाहिता ने अपने पति, सास व ससुर पर घरेलू हिंसा का गंभीर आरोप लगाया। बुधवार सुबह पीड़िता ने कोतवाली पहुंचकर तहरीर दी। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।

विवाहिता ने बताया, पति शराबी है। दिनभर पीकर किसी अन्य लड़की से फोन पर बातें करता। विरोध पर शारीरिक-मानसिक यातनाएं देता। सास-ससुर के इशारे पर प्रताड़ित किया। दो बच्चों को खाना-पानी तक न दिया। सामान मांगने पर मारपीट कर घर से बेघर किया। किसी तरह मायके पहुंची, परिजनों को बताया।

प्रभारी निरीक्षक दिगम्बर सिंह बोले, "तहरीर पर जांच चल रही। दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी।" घटना से इलाके में सनसनी।

कंजा हरैया अशोकनगर कॉलोनी में ट्रांसफॉर्मर से ग्रामीण त्रस्त - गंदगी व शॉर्ट सर्किट से उपकरण खराब, जेई ने सफाई का आश्वासन दिया

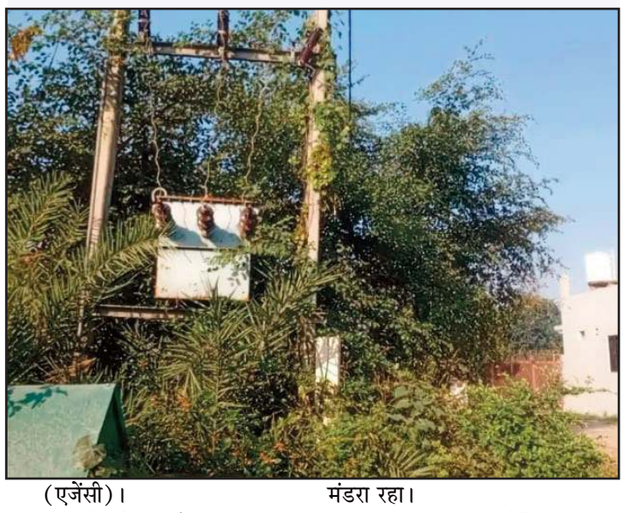

(एजेंसी)।

पीलीभीत के गजरौला कला थाना क्षेत्र के कंजा हरैया में अशोकनगर कॉलोनी के ट्रांसफॉर्मर ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी। आसपास कचरा, झाड़ियां व पेड़-पौधे जमा होने से बार-बार शॉर्ट सर्किट हो रहे। कई घरों के फैन, टीवी जैसे उपकरण जल चुके। बारिश-नमी से हादसे का खतरा मंडरा रहा।

ग्रामीण रामलाल, गोविंद, अजय, रतन, तपन व मनोहर ने शिकायत की झ कई बार बिजली विभाग को बताया, लेकिन कोई ध्यान नहीं। उन्होंने सफाई, मरम्मत व सुरक्षा घेरा लगाने की मांग की। जेई गोपाल सागर बोले, "जांच कर जल्द सफाई कराएंगे।"

ग्रामीणों में गुस्सा।

जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की भारतीय कमांडर निकली लखनऊ की डाक्टरनी

(एजेंसी)।

लखनऊ। दिल्ली में रेड फोर्ट के पास हुए भीषण विस्फोट की जांच में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। मौके पर गिरफ्तार करी गई लखनऊ की "डॉक्टर शाहीन शहीद" न केवल आतंकी साजिश का हिस्सा थी, बल्कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन "जैश-ए-मोहम्मद" की महिला विंग 'जमात-उल-मोमिनात' की भारत में कमांडर भी थी यह भारत के खिलाफ आतंकवाद के इतिहास में एक नया और खतरनाक मोड़ है। लखनऊ की रहने वाली डॉ० शाहीन शहीद को यूपी एटीएस जम्मू-कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। पुलिस के अनुसार, डॉ० शाहीन को भारत में जैश की महिला शाखा स्थापित करने और महिलाओं की भर्ती करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, डॉ० शाहीन शहीद पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद की महिला विंग की प्रमुख "सादिया अजहर" के सीधे संपर्क में थीं। सादिया अजहर, जैश के सरगना "मसूद अजहर" की बहन हैं और मसूद अजहर के भाई "युसूफ अजहर" की पत्नी थीं। "युसूफ अजहर" 1999 में हुई कंधार विमान अपहरण की साजिश का मास्टरमाइंड था, जिसे 7 मई 2025 को भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया था। यह कनेक्शन केवल एक संगठनात्मक संबंध नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क का हिस्सा है। जांच में पता चला है कि "डॉ० शहीद" एन्क्रिप्टेड संचार माध्यमों से पाकिस्तान स्थित हैंडलरों के संपर्क में थीं और उसे जम्मू-कश्मीर, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में महिलाओं की भर्ती का काम सौंपा गया था अक्टूबर 2025 में, जैश-ए-मोहम्मद ने अपने इतिहास में पहली बार 'जमात-उल-मोमिनात' नामक महिला विंग की स्थापना की घोषणा की थी। मसूद अजहर के नाम से जारी एक पत्र में बहावलपुर, पाकिस्तान में 8 अक्टूबर को मरकज उस्मान-ओ-अली में भर्ती शुरू होने की बात कही गई थी। इस महिला ब्रिगेड का नेतृत्व सादिया अजहर कर रही है। सूत्रों के अनुसार, यह संगठन जैश के मारे गये आतंकियों की बेवाओं, और आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को बहावलपुर, कराची, मुजफ्फराबाद, कोटली, हरिपुर और मानसेहरा जैसे शहरों से भर्ती कर रहा है। विशेष रूप से, मसूद अजहर की बहन समीरा अजहर (उम्मे मसूद) और पुलवामा हमलावर उमर फारूक की विधवा

अफीरा फारूक भी इस इकाई के नेतृत्व में शामिल हैं। इस महिला विंग की स्थापना के बाद, मसूद अजहर ने 21 मिनट का एक ऑडियो संदेश जारी किया था, जिसमें उसने महिलाओं को प्रशिक्षण, ब्रेनवॉश और तैनाती की विस्तृत योजना बना के बताई। अजहर ने कहा कि जैसे पुरुषों के लिए 15 दिन का 'दौरा-ए-तारबियत' कोर्स है, वैसे ही महिलाओं के लिए 'दौरा-ए-तस्कीया' नामक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होगा अपने भाषण में, मसूद अजहर ने महिला कैडर से वादा किया कि "जो भी खातून शामिल होगी, वह इंतकाल के बाद अपनी कब्र से सीधे जन्नत में जाएगी"। उसने यह भी कहा कि "जैश के दुश्मनों ने हिंदू महिलाओं को सेना में शामिल किया है और महिला पत्रकारों को हमारे खिलाफ खड़ा किया है"। यह एक सुनियोजित प्रोपोगंडा रणनीति है जो धार्मिक भावनाओं का दुरुपयोग करके महिलाओं को आतंकवाद में शामिल करने का प्रयास है। डॉ० शाहीन शहीद फरीदाबाद के धौज स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई थी। यही वह विश्वविद्यालय है जहां डॉ० मुजम्मिल शकील भी पढ़ाता था, जिसके किराए के कमरे से 360 किलोग्राम (360 किलोग्राम) फ्क़ 14 सूटकेस भरे विस्फोटक, टाइमर, बैटरियां और रिमोट कंट्रोल बरामद हुए थे। अधिकारियों को संदेह है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी की प्रयोगशालाओं का उपयोग उन्नत किस्म के विस्फोटक बनाने के लिए किया जा रहा था। जांचकताओं का कहना है कि यह मॉड्यूल दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी भारत में तीन बड़े आतंकी हमलों की योजना बना रहा था। परंपरागत रूप से, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे दक्षिण एशियाई आतंकी समूहों ने महिलाओं को सक्रिय भूमिकाओं में तैनात करने से परहेज किया था। लेकिन भारत के ऑपरेशन सिंदूर में जैश के मुख्यालय पर हमले के बाद, जिसमें मसूद अजहर के 10 परिवार के सदस्यों की मौत हुई, संगठन ने अपनी रणनीति बदल दी है। आईएसआईएस, बोको हराम, हमास और एलटीटीई जैसे समूहों ने अतीत में महिला आत्मघाती हमलावरों का उपयोग किया है। अब जैश भी इसी रास्ते पर चल रहा है। इस सिलसिले में यूपी एटीएस और जम्मू-कश्मीर पुलिस की लखनऊ के मड़ियांव इलाके में आईआईएम रोड मुतक्कीपुर स्थित डॉक्टर परवेज अंसारी के घर पर भी छापेमारी छापेमारी जारी है। अब भोकाल मचेगा ॐ नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव।

छात्रों ने एक युवक को मामूली कहासुनी से आम के बाग में बेल्ट-लातों से बेरहमी से पीटा, वीडियो वायरल।

(एजेंसी)।

पीलीभीत जोगराजपुर । जनपद के थाना सेहरामऊ उत्तरी क्षेत्र के जोगराजपुर गांव में नवयुवक छात्रों ने गुंडई की ऐसी मिसाल कायम की कि पूरा इलाका दहल गया। सूत्रों से जानकारी के मुताबिक युवक और छात्रों में मामूली कहासुनी हो गई ।जब छात्रों का एक गुट दूसरे युवक से भिड़ गया। देखते ही देखते आधा दर्जन से ज्यादा नवयुग के छात्रों ने एक युवक को आम के बाग में घेर लिया और भयंकर तरीके से हमला बोल दिया। बेल्टों से कोड़े मारे, लातें ठोकीं, घूंसे बरसाए झ युवक को जमीन पर पटककर बेरहमी से पीटा। पूरा वारदात मोबाइल पर रिकॉर्ड हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल होकर ग्रामीणों में डर और गुस्सा फैला रहा है।

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, विवाद किसी छोटी-मोटी बात से शुरू हुआ और विवाद बेहद गंभीर हो गया ।जोगराजपुर कॉलेज के छात्र, जो

घूम रहे थे, किसी स्थानीय युवक से उलझ पड़े। बात बढ़ते ही फिल्मी इंस्टाइल में युवक को बेरहमी से बेल्टों से जमकर पीटा, युवक को गंभीर रुप से घायल हो गया।

छात्रों के इस रवैया से ग्रामीण बेहद नाराज हैं अगर छात्रों के साथ कोई कहा सुनी हुई थी तो छात्रों को शासन प्रशासन का सहारा लेना चाहिए था ना की फिल्मी स्टाइल में युवक को लात घुसा और बेल्टों से मारा चाहिए था?।

क्या इस छात्रों के इस रवैया से युवक की जान चली जाती तो एक बड़ी घटना हो सकती थी?

मामले का वीडियो वायरल होने के बाद क्षेत्र में तरह-तरह की चचाएं हो रही हैं

हालांकि वीडियो में साफ तोर से स्पष्ट नजर आ रहा है झ युवक जमीन पर गिरा पड़ा है, चीख रहा है, लेकिन ऊपर 6-7 छात्र मिलकर पिटाई कर रहे हैं। एक छात्र बेल्ट निकालकर मार रहा, दूसरे लातें ठोक रहे, तीसरा बाल खींच रहा। ग्रामीण दौड़े-दौड़े आए और बीच-बचाव करने लगे, लेकिन तब तक युवक के चेहरे-शरीर पर गंभीर चोटें लग चुकी थीं ।छात्रों तुरंत मौके से भाग निकले।

थाना सेहरामऊ पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है

साहित्य अकादमी-बाल साहित्य पुरस्कार 2025

(एजेंसी)।

साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य की विधा में वार्षिक पुरस्कार - बाल साहित्य पुरस्कार 2025, शुक्रवार, 14 नवंबर 2025 को नई दिल्ली के तानसेन मार्ग स्थित त्रिवेणी सभागार में प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक द्वारा प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रख्यात गुजराती लेखिका वर्षा दास मुख्य अतिथि होंगी और अकादमी की उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा धन्यवाद ज्ञापन करेंगी। साहित्य अकादमी की सचिव पल्लवी प्रशांत होल्कर स्वागत भाषण देंगी।

पुरस्कृत पुस्तकें और पुरस्कार विजेता हैं: असमिया - मैनाहंतार पद्य (कविता), सुरेंद्र मोहन दास; बंगाली - एखोनो गए कांता दये (कहानियां), त्रिदीब कुमार चट्टोपाध्याय; बोडो - खांथी ब्स्वन अर्व अखु दानई (कहानियां), बिनय कुमार ब्रह्म; डोगरी - नन्हीं तोर (कविता), पीएल परिहार 'शौक'; अंग्रेजी - दक्षिणः साउथ इंडियन मिथ् स एंड फैबल्स रिटोल् ड (कहानियां), नितिन कुशलप्पा एमपी; गुजराती - तिनचक (कविता), कीर्तिदा ब्रह्मभट्ट; हिंदी - एक बटे बारह (नॉन-फिक्शन और संस्मरण), सुशील शुक्ला; कन्नड़ - नोटबुक (लघु कथाएं), के. शिवलिंगप्पा हंडीहाल; कश्मीरी - शुरे ते त्चुरे ग्युश (लघु कथाएं), इजहार मुबाशिर; कोंकणी - बेलाबाईचो शंकर अनी वारिस कान्यो (कहानियां), नयना अदारकर; मैथिली - चूक्का (लघुकथाएं), मुन्नी कामत; मलयालम - पेंगुइनुकालुडे वंकाराविल (उपन्यास), श्रीजीत मूथेदथ; मणिपुरी - अंगांगशिंग - जी शन्नाबुंगशिदा (नाटक), शान्तो एम.; मराठी - अभयमाया (कविता), सुरेश गोविंदराव सावंत; नेपाली - शांति वन (उपन्यास), संगमू लेप्चा; उड़िया - केते फुला फूटिची (कविता), राजकिशोर पारही; पंजाबी - जद्दू पत्ता (उपन्यास), पाली खादिम (अमृत पाल सिंह); राजस्थानी - पंखेरुव नी पीड़ा (नाटक), भोगीलाल पाटीदार; संस्कृत - बलविस्वम (कविता), प्रीति आर. पुजारा; संताली - सोना मिरू-अग संदेश (कविता), हरलाल मुर्मू; सिंधी - आसमानी परी (कविता), हीना अगनानी 'हीर'; तमिल - ओट्राई सिरगु ओविया (उपन्यास), विष्णुपुरम सर्वानन; तेलुगु - काबुरला देवता (कहानी), गंगीसेट्टी शिवकुमार; उर्दू - कौमी सितारे (लेख), गजनफर इकबाल।

पुरस्कार विजेताओं को उनके कार्यों के सम्मान में 50-50 हजार रुपये का चेक और एक कांस्य पट्टिका प्रदान की जाएगी।

अगले दिन अर्थात 15 नवंबर 2025 को अकादमी के नई दिल्ली के फिरोजशाह रोड स्थित सभागार रवींद्र भवन में पुरस्कार विजेताओं की बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में पुरस्कार विजेता अपने रचनात्मक अनुभवों पर विचार-विमर्श करेंगे, जिसकी अध्यक्षता अकादमी की उपाध्यक्ष कुमुद शर्मा करेंगी।

ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इण्टीट्यूट में परिवहन आयुक्त ने किया प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ

सभी जनपदों में मानक अनुरूप लिये जाये ड्राइविंग टेस्ट- परिवहन आयुक्त

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा वाहन चालकों के प्रशिक्षण एवं दक्ष चालकों को ही ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त हो, के उद्देश्य से प्रदेश के कई जनपदो में ड्राइविंग ट्रेनिंग एण्ड टेस्टिंग इण्टीट्यूट (डीटीटीआई) स्थापित किये गये हैं जिसमें अयोध्या डीटीटीआई भी एक है।

अयोध्या, (एजेंसी)।

दिनांक 12 नवंबर, 2025 को मथुरा, अयोध्या एवं वाराणसी के

परिवहन विभाग के अधिकारियो व कर्मचारियों हेतु एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसका शुभारंभ मुख्य अतिथि परिवहन आयुक्त महोदया श्रीमती किंजल सिंह द्वारा दीप प्रज्जवलन करके किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन आरटीओ प्रशासन सुश्री ऋतु सिंह के नेतृत्व में किया गया। परिवहन आयुक्त महोदया द्वारा शासन की सभी योजनाओं को जनहित में सफलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु प्रेरित किया एवं डीटीटीआई का निरीक्षण कर ड्राइविंग टेस्ट आटोमेटेड टेस्टिंग ट्रैक पर टेस्ट लिये जाने की प्रक्रिया और तत्पश्चात ड्राइविंग लाइसेंस जारी किये जाने के फ्लो को समझा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना की व अधीनस्थों को आवश्यक निर्देश दिये।

सर्वप्रथम आरटीओ सुश्री ऋतु सिंह द्वारा परिवहन आयुक्त महोदया को मोमेंटो व पुष्पगुच्छ भेंट कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आरटीओ ने सबका स्वागत करते हुए सड़क सुरक्षा एवं ड्राइविंग ट्रेनिंग इण्टीट्यूट की प्रणाली में सभी अधिकारियों व कर्मचारियो को भली-भाँति परिचित कराने के उद्देश्य एवं अयोध्या में संचालित किये जा रहे विभिन्न महत्वपूर्ण अभियानों, जागरुकता कार्यक्रमों पर प्रकाश डाला।